

महत्वपूर्ण एवं खास

विदेशी निवेश पर भरोसा

लगता है देश में विकास को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का मन बना लिया है। स्मार्ट सिटी योजना समेत अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिये जिस पूँजी की जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दरवाजे खोले जा रहे हैं। यही बजह है कि जिन नीतियों का विपक्ष में रहते भाजपा विरोध करती रही है, उसी राह पर राजग सरकार ने कदम बढ़ा दिये हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर जो फैसले लिये हैं, उसके पार्श्व में 2019 के आम चुनाव भी हैं ताकि वायदे हकीकत में बदलते दिखाये दें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बावजूद अपेक्षित विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के बाद सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गस्ता खोल दिया है। अभी तक इसके लिये सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। साथ ही सरकार पर बोझ जाएगा।

आय पर टैक्स की कैफी

अपने पिछले बजट में वित्तमंत्री इसमें आधारभूत कर का प्रसार अरुण जेटली ने कोशिश की थी कि निजी आयकर प्रणाली को ज्यादा उत्तराधीन बनाया जाए ताकि लोगों को पेरेशानी भी न हो और कर के नाम से जो मन में डर बैठा है, वह भी दूर हो जाए। इसका सीधा असर कर वसूली के अंकड़े में देखने को मिला जो दिसंबर 2017 तक उछलकर 18 फीसदी तक जा पहुँचे। उनके इस पास से सबसे बड़ा फायदा निम्नतर आयकर स्लैब यानी ढाई से 5 लाख रुपए वाले करदाताओं को हुआ, जिनकी दर मज़ज़ यांच फीसदी तक सीमित थी। इस स्लैब वाले पहली बार के करदाताओं को कागजों की पूँछ-पड़ताल आदि से भी छुप्पी थी। आयकर दर को ज्यादा तर्कसंगत तथा आयकर प्रशासन को ज्यादा उत्तराधीन बनाने के लिए। कर अधिकारियों के पास अब लगभग 35 करोड़ पैसे कार्ड हैं जो कार्ड होल्डरों के बैंक से बढ़िया काम यह किया कि यह सीधे जुड़े हैं।

शब्द सामर्थ्य Shabd Samarth

बाएं से दाएं

- संघर्ष, दौड़ीधूप (उर्दू)
- सुपुत्र, लायक पुत्र
- ताकतवर, बलशाली
- खुशबू, सुरभि, सुगंध
- अकारण, व्यथ, बेवजह
- गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना
- यात्रा
- मृत, जो मर गया हो
- छोटे कद का, वामन, बौना
- सांप का सिर, गुण, कला, कौशल
- निरुत्तर,

बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला

- एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली
- माता, जननी
- संतान, औलाद
- अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी
- चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे

- पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित
- पाकेटमार, जेब काटने वाला
- समाधान, खेत जोतने का यंत्र
- रहता है
- बुद्धि, दिमाग।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 91 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म	स
ट	भ	ला	ई	अ	स	म
ना	म			स	मा	धि
ज		बे		न	का	र
बा	बू	आ	य	क	र	
र	की	ब				प्रथा
ज		रू	प	क		ज
हा		पा	ना	म	ची	न
ज	हां	प	ना	ह	ता	न

संपादकीय

इराने वाली बेकारी की लाचारी

राजस्थान विधानसभा सचिवालय में चपरासी के सत्रह पदों की रिकियों के लिए साढ़े बारह हजार लोगों द्वारा प्रार्थनापत्र भेजना अपने आप में एक चौकाने वाला समाचार है। लेकिन इस समाचार की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह पता चलता है कि चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए उमीदवारों में 129 इंजीनियर, 23 वकील, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, 393 साकातकार और डेंड हजार से अधिक साकातक हैं। और जब यह पता चलता है कि चपरासी के पद के लिए आवश्यक अर्हता मात्र पांचवीं पास होना है तो स्थिति की गंभीरता और विडंबना दोनों सामने आ जाती है। जहां ये अंकड़े देश में लगभग 178 लाख थी, जिसके 2018 में भारत में रोजगार नहीं मिल पा रहा। घोषणाएं ते बहुत बड़ी-बड़ी होती रही हैं इस वीच, आकर्षक योजनाओं की भी कमी नहीं है डूँकौशल विकास से लेकर स्टार्टअप और जॉब ऑफिस के लिए आवश्यक अर्हता तक नहीं है। और जब यह पता चलता है कि चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए उमीदवारों में योग्यान्वयन के लिए विदेशी निवेश के लिए फैसले लिये हैं, उसके असर इन विदेशी निवेश को लेकर जो फैसले लिये हैं, उसके पार्श्व में 2019 के आम चुनाव भी हैं ताकि वायदे हकीकत में बदलते दिखाये दें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बावजूद अपेक्षित विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के बाद सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गस्ता खोल दिया है। अभी तक इसके लिये सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। साथ ही सरकार पर बोझ जाएगा।

विधानसभा सचिवालय में चपरासी के लिए अनुबंध वाले रोजगार को बढ़ावा दिया गया। अभी तक यह केवल निजी विमान कंपनियों में संभव था। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अब एर इंडिया में और सार्वजनिक पूँजी लगाना अकलमंदी नहीं है। बहरहाल, इसमें आशा जगी है कि अब एर इंडिया का विकास पेशेवर तरीके से हो यायेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार को संरक्षण देना भी है, जिसमें एक बड़ी आवादी को रोजगार मिला है। वहीं एकल ब्रांड खुदरा कारोबार को संरक्षण देना भी है, जिसमें एक बड़ी आवादी को रोजगार मिला है। जहां ये अंकड़े देश में लगभग 178 लाख थी, जिसके 2018 में भारत में रोजगार नहीं मिल पा रहा। घोषणाएं ते बहुत बड़ी-बड़ी होती रही हैं इस वीच, आकर्षक योजनाओं की भी कमी नहीं है डूँकौशल विकास से लेकर स्टार्टअप और जॉब ऑफिस के लिए आवश्यक अर्हता तक नहीं है। और जब यह पता चलता है कि चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए उमीदवारों में योग्यान्वयन के लिए विदेशी निवेश के लिए फैसले लिये हैं, उसके असर इन विदेशी निवेश को लेकर जो फैसले लिये हैं, उसके पार्श्व में 2019 के आम चुनाव भी हैं ताकि वायदे हकीकत में बदलते दिखाये दें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बावजूद अपेक्षित विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के बाद सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गस्ता खोल दिया है। अभी तक इसके लिये सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। साथ ही सरकार पर बोझ जाएगा।

विधानसभा सचिवालय में चपरासी के लिए अनुबंध वाले रोजगार को बढ़ावा दिया गया। अभी तक यह केवल निजी विमान कंपनियों में संभव था। सरकार इस परिणाम है कि स्नातक, स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग जैसे प्रशिक्षण प्राप्त युवा चपरासी बनने के लिए आवश्यक नहीं हैं। लेकिन यहां में योग्यान्वयन के लिए अनुबंध वाले रोजगार नहीं हैं। और जब यह पता चलता है कि चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए उमीदवारों में योग्यान्वयन के लिए विदेशी निवेश के लिए फैसले लिये हैं, उसके असर इन विदेशी निवेश को लेकर जो फैसले लिये हैं, उसके पार्श्व में 2019 के आम चुनाव भी हैं ताकि वायदे हकीकत में बदलते दिखाये दें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बावजूद अपेक्षित विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के बाद सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गस्ता खोल दिया है। अभी तक इसके लिये सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। साथ ही सरकार पर बोझ जाएगा।

विधानसभा सचिवालय में चपरासी के लिए अनुबंध वाले रोजगार को बढ़ावा दिया गया। अभी तक यह केवल निजी विमान कंपनियों में संभव था। सरकार इस परिणाम है कि स्नातक, स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग जैसे प्रशिक्षण प्राप्त युवा चपरासी बनने के लिए आवश्यक नहीं हैं। लेकिन यहां में योग्यान्वयन के लिए अनुबंध वाले रोजगार नहीं हैं। और जब यह पता चलता है कि चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए उमीदवारों में योग्यान्वयन के लिए विदेशी निवेश के लिए फैसले लिये हैं, उसके असर इन विदेशी निवेश को लेकर जो फैसले लिये हैं, उसके पार्श्व में 2019 के आम चुनाव भी हैं ताकि वायदे हकीकत में बदलते दिखाये दें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बावजूद अपेक्षित विदेशी निवेश हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के बाद सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और भवन निर्माण के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गस्ता खोल दिया है। अभी तक इसके लिये सरकार से विशेष